भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 840
(25 जुलाई, 2023 को उत्त8र दिए जाने के लिए)

केरल में एमजीएनआरईजीएस

840. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामग्री घटक के रुप में केरल राज्य पर (एमजीएनआरईजीएस) 220 करोड़ रुपए लंबित हैं, और यदि हां, तो उसका विवरण और उस पर की गई कार्रवाई क्या है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि मनरेगा के सामग्री घटक प्रदान करने में देरी के कारण, निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने में उदासीनता के कारण रास्ते और गौशालाओं सहित कई निर्माण कार्यों को या तो छोड़ दिया गया है या अनावश्यक देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है :

(ग) क्या यह सच है कि केरल में मनरेगा के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में जुड़े और नियुक्त कार्यालय कर्मचारियों का वेतन घटक अप्रैल 2023 से लंबित है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का सामग्री घटक के भुगतान में तेजी लाने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 (21.07.2023 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन के लिए केरल राज्य को 1207.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है , जिसमें सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 423.67 करोड़ रुपए शामिल हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियां जारी करने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय ''सहमत'' श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति , लंबित देयताओं, समग्र निष्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर दो खेपों में आवधिक रूप से निधियां जारी करते हैं जिनमें प्रत्येक खेप में एक या अधिक किश्तें होती हैं ।

****